दस हजार मेगावाट क्षमता के बैटरी ऊर्जा स्टोरेज संयंत्र लगाने की प्रक्रिया जल्द

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज (एसईएस) संयंत्र लगाने के पहले चरण पर काम शुरू करने जा रही है। पहले चरण में देश में 10 हजार मेगावाट क्षमता के एसईएस लगाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। बैटरी पर आधारित ये बेहद अत्याधुनिक किस्म के ऊर्जा स्टोरेज संयंत्र होंगे, जो राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े होंगे। जरूरत के हिसाब से इनसे बिजली की आपूर्ति ली जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव विजय मित्तल के मुताबिक, एनर्जी स्टोरेज संयंत्र लगाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग के साथ एक वृहद योजना पर काम हो रहा है।

इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (आइईएसए) की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में मित्तल ने बताया कि सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए जरूरी बैटरियों के

ग्रिड से जुड़े होंगे यह ऊर्जा स्टोरेज संयंत्र, वर्ष 2032 तक देश में नौ लाख मेगावाट क्षमता की लीथियम बैटरी की होगी मांग

घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन करने की नीति लागू कर चुकी है। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। जिस तेजी से भारत में ईवी का प्रचलन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए वर्ष 2032 तक 6-9 लाख मेगावाट क्षमता की लीथियम बैटरी बनानी होंगी। सरकार की मदद से तकरीबन 40 हजार मेगावाट क्षमता के बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र लगाने पर काम शुरू हो चुका है।

दरअसल, भारत में सिर्फ सरकार के स्तर पर ही बैटरी निर्माण का काम नहीं हो रहा, बल्कि कई लैब और स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय शोध कर रहे हैं। लिथियम प्रौद्योगिकी की क्षमता को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। आइईएसए का कहना है कि हाल ही में लीथियम सल्फर पर आधारित प्रौद्योगिकी को लेकर भारतीय स्टार्टअप ने काफी संभावनाओं वाली प्रगति की है। तीन-चार वर्ष पहले तक बैटरी निर्माण की अधिकांश क्षमता चीन में ही लग रही थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वैश्विक कंपनियां भारत को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही हैं। चीन की मौजूदा बैटरी निर्माण क्षमता नौ लाख मेगावाट है। भारत यह क्षमता अगले छह-सात वर्षों में हासिल करने की मंशा रखता है। इससे साफ पता चलता है कि चीन कितना आगे है। भारत में ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली 85 प्रतिशत से ज्यादा बैटरियां चीन से आ रही हैं।